for abatement of Pollution in the grossly polluted stretches of major rivers of the country is in the final stages of formulation. Details in this regard are being worked out.

मध्य प्रदेश में साहस भरे काम करने वाले वन कार्मिकों को बारी से पहले पदोन्नति

259. **श्री कैलाश नारायण सारंग** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश के वन विभाग में साहसपूर्ण काम करने वाले वन कार्मिकों को बारी से पहले पदोन्नतियां दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कार्मिक हैं जिन्हें ऐसी पदोन्नतियां दी गयी हैं और ऐसे कितने साहसिक कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के मामले मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन हैं, इन वन कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) ऐसे वन कार्मिकों को बारी से पहले पदोन्नतियां न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन्हें कब तक पदोन्नतियां दे दी जायेंगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण रखने हेतु योजनाएं

259. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण रखने हेतु 31 योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं और ये किन-किन क्षेत्र से संबंधित हैं ; और

(ग) इस दिशा में इस परियोजना पर कितना कार्य हो चुका है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास अनेक स्कीमें हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- जल प्रदूषण (उपकर) निवारण एवं नियंत्रण;
- पर्यावरणीय संपरीक्षा ;
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायतानुदान;
- प्रदूषण नियंत्रण (वह्य सहायता प्राप्त स्कीम);
- सांझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढ़ावा देना;
- पर्यावरणीय आंकड़े तथा मानचित्रण;
- प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता;
- परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन;
- लघु उद्योगों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियां;
- विशेष मदों पर उत्पाद और सीमा-शुल्क में छूट सहित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।

ये स्कीमें सरकार की जारी गतिविधियों के अन्तर्गत आती हैं।

इसके अलावा, 261 स्कीमें हैं जिन्हें गंगा के प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत मंजूर किया गया है।

गंगा कार्य योजना के अंतगत 261 मंजूर स्कीमों में से 208 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

Agreements signed with Oman

260. SHRI P. UPENDRA: Will the *Minister of EXTERNAL AFFAIRS* be pleased to state:

(a) whether any agreements were signed with Oman during the recent visit of the Prime Minister to that country; and

(b) what are the details of the deals finalised during the visit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Yes, Sir. Two agreements and an MOU were signed with Oman during the recent visit of the PM to that country. These are:

(i) Agreement on Economic, Trade and Technical Cooperation which envisages setting up of a Joint Commission.

(ii) Agreement on Cooperation in the Field of-Hydro-carbons to provide strong impetus to mutually beneficial proposals to promote and facilitate investment proposals in the field of Hydro-carbons sectors, Fertilizers and other areas.

(iii) MOU on Cooperation in the field of Fertilizers, for setting up of a proposed joint venture Ammonia-Urea fertilizer project in Oman.

(b) No deals in addition to the agreements listed above were signed.

Pressler Amendment

261. SHRI SURESH PACHOURI:

SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether US congressional research service report has complained that the Pressler Amendment favour India, and favour modifications of the NPT to accommodate the sensitivity of nuclear power like India and Pakistan;

(b) if so, whether India has considered these amendments;

(c) to what extent these amendments have favoured India and whether Government of India consider to sign NPT; and

(d) if so, by when Indian Government will take a final decision in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) The Congressional Research Service Report "South Asia: US Interests and Policy Issues" (dated February 12, 1993) authored by Richard P. Cronin and Barbara Leitch LePoer, states that "some observers now see the Pressler amendment as having outlived its usefulness". The report also states that some shift of US nuclear policy would